(ख) क्या वित्त मंत्रालय से परामर्श करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो के किसी अधिकारी को उनके उत्पादन की जांच करने के लिए कहा जायेगा;

(ग) क्या यह जांच उनके बही खातों पर छापा मारकर कराई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Encouragement of Exports by States

3361. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are encouraging exports from all States to overcome its balance of payments problems;

(b) if so, what is the annual value of exports from each State during the Sixth and Seventh Five Year Plan periods, State-wise;

(c) whether Government have received any proposal for establishment of an Export Processing Zone in Karanataka aimed at facilitating exports;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) whether Government would clear this proposal at the earliest?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes, Sir.

(b) State-wise export data are not compiled.

(c) to (e) A proposal for setting up export processing zones in Bangalore and Mangalore has been received. The Government does not intend to set up any new free trade zone till the facilities created at the six existing export processing zones and the proposed zone at Vishakhatnam are fully utilised, and a carefull study of the existing zones is carried out.

आर्थिक विकास के लिए सरकार की पहल

3362. **श्री राम अवधेश सिंह**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए कोई पहल कर रही है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समान एशिया में एक सांझा बाजार की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) से (ग) भारत सरकार और साथ ही साथ उसी प्रकार के दृष्टिकोण वाले अनेक गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों ने 1989 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुए 9 वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण-दक्षिण परामर्श एवं सहयोग संबंधी शीर्ष स्तरीय समूह (जिसे जी-15) कहा जाता है स्थापित करने के लिए पहल की थी। जी-15 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए ठोस योजनाएं तैयार करना तथा उन्हे अपनाना और ऐसी योजनाओं के पक्ष में विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त करना शामिल है। पहली दो शिखर बैठकों से जी-15 देशों के बीच सहयोग के लिए संस्थागत आधार बनाने में मदद मिली। विशेष परियोजनाओं का पता लगाया गया और उनके कार्यान्वयन के समन्वय का उत्तरदायित्व देशों को सौंपा गया। भारत इन परियोजनाओं में से दो के लिए, अर्थात जेने बैंक फार मैडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स एवं हर्ब्स तथा सोलर एनर्जी एप्लीकेसन्स, के लिए उत्तरदायी है।

भारत त्रिपक्षीय करार, बैंकाक करार, गाट संलेख और व्यापार अधिमानों को विश्वव्यापी प्रणाली (जी॰एस॰टी॰पी॰) का हस्ताक्षरकर्त्ता है। ये चारों ही विकासशील देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध के लिए भी एक प्रस्ताव है जिस पर सार्क देश विचार कर रहें है।

भारत-श्रीलंका व्यापार समझौता

3363. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या-क्या

है और दोनों देशों के बीच किन-किन वस्तुओं का व्यापार किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि, लघु उद्योग तथा तेल के अन्वेषण में संयुक्त उद्यमों के लिए कार्य क्षेत्र का पता लगाने के अतिरिक्त, द्विपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्यिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर बल दिया गया था।

Export target of rice

3364. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any target has been fixed for the export of rice during the current year;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether this target is likely to be achieved;

(d) if not, what are the reasons therefor; and

(e) what measures Government propose to take to meet the target?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) and (b) In value terms, target fixed for export of rice for the current year is Rs. 700 crores.

(c) Yes, Sir.

(d) Queustion does not arise.

(e) Government has already taken various promotional measures, removed constrains, and simplified procedures for exports.

Procurement of Iron-Ore from Orissa mines for export

3365. SHRI JAGDISH JANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) What is the total quantum of iron ore procured annually for export purposes from Barajamda, Banspani and Gandhamardhan sector in Orissa;

(b) what are the details thereof during the last three years– year-wise;

(c) whether there has been a sharp decline in the procurement of iron ore;

(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) what steps are being taken to increase the procurement of iron ore and export from these services?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The total quantum of iron ore procured annually for export purposes from Barajamda, Banspani, Gandhamardhan and Daitari sectors during the last three years is given below:

Qty. Lakh Tonnes

Year	Barajamda Sector (Bihar)	Banspani Sector	Gandhamardhan Sector including OMC (Orissa)	Daitari (OMC)	Total
1988-89	0.89	7.86	1.69	0.81	11.25
1989-90	1.65	10.80	1.48	1.12	15.05
1990-91	2.22	15.28	1.59	1.97	21.06

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) MMTC has been attempting to maximise the output of iron ore from these sectors by offering incentives to promote scientific and systematic development of mines.

Export of Plastic

3366. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government will be able to export plastic to other countries in view of its bulk production in the country during the year 1992-93; and